



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

० 118] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 1976/फाल्गुन 19, 1897  
 ३. 118] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 1976/PHALGUNA 19, 1897

इस भाग में भिन्न १६५ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
 as a separate compilation

## MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 9th March 1976

**S.O. 183(E).**—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Heavy Industry) No. S.O. 146(E) dated the 14th March, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments entered into, given or made, as the case may be before 15th February, 1974, to which the industrial undertaking known as M/s. Britannia Engineering Works (Wagons Division), Mokameh, in the State of Bihar or the company carrying out such undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company and in force immediately before the date of issue of said Order shall remain suspended upto the 18th March, 1976, and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 18th March, 1976;

And Whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order could be extended for a further period up to the 18th March, 1977;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 18th March, 1977.

[No. F. 4/2/73-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

## उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

## (औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1976

का० आ० 183 (अ).—भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के आदेश सं० का० आ० 146 (अ), तारीख 19 मार्च, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 खख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि 15 फरवरी, 1974 से पूर्व यथास्थिति, की गई या दी गई सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का, जिनका बिहार राज्य में मेसर्स ब्रिटैनिया इंजीनियरिंग वर्क्स (वैंगन्स डिविजन), मुकामा नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों और जो उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, प्रवर्तन 18 मार्च, 1976 तक निलम्बित रहेगा, और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व 18 मार्च, 1976 तक निलम्बित रहेंगे;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 18 मार्च, 1977 तक और बढ़ाई जानी चाहिए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 खख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 18 मार्च, 1977 तक बढ़ाती है।

[सं० फा० 4/2/73-सी० यू० सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।